

राजस्व अपील संख्या 133/2022

अनवान

इन्द्राराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेतरावा

दिनांक 29 -03-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/595 दिनांक — के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री पूनाराम विश्‍नोई रेस्पो० की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित । तथा केवियटर श्री भंवरसिंह टापू उपस्थित । केवियटर अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का उक्त अपील में पक्षकार बनाने बाबत प्रस्तुत किया।

अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर पक्षकारों के अधिवक्ता एवं प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहनता से अध्ययन किया जिसके आधार पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री भंवरसिंह टापू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

वर्तमान अपील में अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाल दिया तथा अपीलांट के खातेदारी की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नहीं किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बन्धी जारी परिपत्र में भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नहीं होने से उसे निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।



गति गम्भाराय बाबु
बोधपुर

अप्रार्थी अधिवक्ता श्री टापू ने मौखिक कथन किया कि पक्षकारो मध्य आपसी राजीनामा का प्रयास चल रहा है तथा राजीनामा हो जाने की सम्भावना है। तब तक अपील को पेडिंग रखी जाने का निवेदन किया। जिस पर अपीलान्त अधिवक्ता ने ऐसा कोई राजीनामा होने की जानकारी नहीं होना बताया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम कालूसिह नगर तहसील सेतरावा के संबंध में पारित किये गये आदेश क्रमांक 595 दिनांक — एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्त की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/595 दिनांक — को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्त, रेस्पोंड प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी में उल्लेख अनुसार एवं हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति में रास्ते बाबत मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह में सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि में से रास्ते के सम्बन्ध में पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश में वर्णित अपीलान्तगण के खातेदारी के खंसरा नं. 154 की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

